

सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 4,69,820 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 2,19,815 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 6,62,415 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 1,94,114 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 32,111 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 8,060 हितग्राही लाभान्वित।
- नर्सिंग प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर तक अनुसूचित जाति के 288 तथा अनुसूचित जनजाति के 497 विद्यार्थी लाभान्वित।
- हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर तक अनुसूचित जाति के 26 तथा अनुसूचित जनजाति के 08 छात्र-छात्राएं लाभान्वित।
- जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के 273 तथा अनुसूचित जनजाति के 535 विद्यार्थी लाभान्वित।

समाज सेवा

16 समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ-साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील हैं।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :- राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रुपये 350/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :-

- 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे, जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत नहीं हैं उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :- योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रुपये 350/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:- योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राशि रुपये 350/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है—

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –
 - घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
 - प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
 - पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
 - बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :- राज्य में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रु. 350 /- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रु. 650 /- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रु. 150 /- राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रुपये 350 /- प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रु. 50 /- राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :- यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रुपये 500 /- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रुपये 200 /- राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :- योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरुष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक / आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रुपये 20,000 /- की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

तालिका 16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति				
योजना	2020-21		2021-22 सित. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख रु.	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख रु.	भौतिक उपलब्धि/ हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	34149.32	469820	16849.26	464224
सुखद सहारा योजना	9527.15	219815	4646.70	218981
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	17221.86	455825	10203.81	492995
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	24802.03	662415	9406.75	652723
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	8836.12	194114	3602.88	195730
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1514.23	32111	600.03	31778
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1681.55	8060	782.38	3838

16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :- निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण-प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना:- इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रु. 150 से 190 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रु. 100 प्रतिमाह वाचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना:- इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रु. 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रु. 5,001 से रु. 8,000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकतम राशि रुपये 6,900/- तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :-प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों हेतु मेले/शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम राशि रुपये 6,900/- तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :- निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरुष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रुपये 50,000/- तथा दोनों (वर-वधू) के निःशक्त होने पर राशि रुपये 1,00,000/- की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं:- विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण-प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित है।

16.2.7 निःशक्तजनों के लिए “क्षितिज अपार संभावनाएं” अन्तर्गत एकीकृत योजना :- प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए “क्षितिज अपार संभावनाएं” नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई हैं।

16.2.7.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

दिए जाने वाले लाभ :-

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रुपये 2,000/- एकमुश्त।
 - जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रुपये 5,000/- एकमुश्त।
 - आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/-रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
 - चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उच्च शिक्षा हेतु 74 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य निःशक्त व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिए जाने वाले लाभ :-

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 20,000 / – एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रुपये 30,000 / – एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रुपये 50,000 / – एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8 निःशक्त प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :-

05 बच्चों के समूह को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

- 1- A श्रेणी के शहर हेतु 10,000 / – (दस हजार) तक देय होगी।
- 2- B श्रेणी के शहर हेतु 7,000 / – (सात हजार) तक देय होगी।
- 3- C श्रेणी के शहर हेतु 5,000 / – (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत 5 निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

तालिका 16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति				
योजना	2020-21		2021-22 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	733.61	2770	121.67	2272
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	235.80	14181	4.41	504
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	86.96	1695	21.83	321
सामर्थ्य विकास योजना	282.60	2333	71.15	529
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	254.50	389	83.50	156
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं	1314.84	1097	655.46	956

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :- वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष “अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस” जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 30 वृद्धाश्रम संचालित है। जहाँ 744 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्था के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 03 प्रशामक देखरेख गृह का संचालन किया जा रहा है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :- योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर यात्रा करायी जा रही है।

16.3.3 तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना :- उभय लिंगी (तृतीय लिंग) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :- 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार अधिकतम रुपये 6,900/- तक के डायबिटिक शू, नी-स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसिस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

तालिका 16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति				
योजना	2020-21		2021-22 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	309.28	21671	32.76	744
तीरथ-बरत योजना	0	0	0	0
तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम/योजना	48.39	2919	2.00	2919
प्रशामक देखरेख गृह	29.92	31	6.00	31

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1 विशिष्ट संस्थाएं :-

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,635 प्री.मैट्रिक, पिछड़ा वर्ग के 08, प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जनजाति के 302, पोस्ट मैट्रिक तथा पिछड़ा वर्ग के 19 संचालित हैं एवं प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं।

प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की आश्रम शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरुकुल (आदर्श) विद्यालय, 71 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, 09 प्रयास, 01 आस्था गुरुकुल विद्यालय एवं 19 क्रीड़ा परिसर संचालित हैं।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभावान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नयी सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है, योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष कक्षा 6 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 विद्यार्थियों इस प्रकार दोनो वर्गों हेतु कुल 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.4 में दर्शित है।

तालिका 16.4 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	273	-
	अनुसूचित जनजाति	535	-
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	273	233.74
	अनुसूचित जनजाति	535	413.77
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	201	-
	अनुसूचित जनजाति	424	-

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :- नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय केन्द्र स्थापित किया गया है। इन विषयों की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में प्रारम्भ

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

की गई है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर गठित हेतु वाणिज्य हेतु बीएड हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदों एवं आयोजित की जाने वाली प्रीबीएड तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु ऑपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगिता अन्तर्गत 500 सीटर बलिकाओं को प्रदाय हेतु दुर्ग जिला के मुख्यालय में 2013-14 में प्रारम्भ की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.5 में दर्शित है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	590	11.22
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	590	44.46
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	594	-

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :- कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- आय-सीमा— रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :-

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)				
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1— (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा—एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाइन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम) (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा— डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550	13500	7000
समूह-2— (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे— फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे— रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्प्यूनिकेशन, ट्रेवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज-सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वि.ती.सी. सेवाएं जैसे— बैंकिंग, इन्श्योरेंस इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे— एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	9500	6500
समूह-3— स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे— बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.एड इत्यादि	570	300	6000	3000
समूह-4 — सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा— रु. 1,00,000/- तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :—

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)					
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रुपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1 – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
2 – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
3 – सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कॉमर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
4 – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
5 – कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:—

तालिका 16.8 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	—
	अनुसूचित जनजाति	—	—
	पिछड़ा वर्ग	—	—
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	56306	3774.83
	अनुसूचित जनजाति	66049	4136.35
	पिछड़ा वर्ग	156843	8610.23
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	ऑन-लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :— अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गों के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक छात्रावास संचालित हैं, इन छात्रावासों में छात्र- छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,633 प्री.मैट्रिक, पिछड़ा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के 392 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछड़ा वर्ग के 19 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। प्री.मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.9 में दर्शित है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 16.9 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	827.64
	अनुसूचित जनजाति	—	3617.85
	पिछड़ा वर्ग	—	22.00
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	827.64
	अनुसूचित जनजाति	—	3617.85
	पिछड़ा वर्ग	—	22.00
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	909.81
	अनुसूचित जनजाति		3657.12
	पिछड़ा वर्ग		22.00

16.4.6 आश्रम शाला योजना :- प्रदेश में वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती है। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.10 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.10 आश्रम शाला योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	172.57
	अनुसूचित जनजाति	—	4193.53
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	172.87
	अनुसूचित जनजाति	—	4193.53
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	206.53
	अनुसूचित जनजाति		4409.24

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना:-खाद्यान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ-साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.11 में दर्शित है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 16.11 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	180.00
	अनुसूचित जनजाति	—	960.00
	पिछड़ा वर्ग	—	9.00
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	180.00
	अनुसूचित जनजाति	—	960.00
	पिछड़ा वर्ग	—	9.00
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	292.50
	अनुसूचित जनजाति		1872.00
	पिछड़ा वर्ग		14.60

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :- विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी जो कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं फलस्वरूप परीक्षा परिणाम में अपेक्षित स्तर पर कमी रहती है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रावास / आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे – गणित/विज्ञान/वाणिज्य इत्यादि विषयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का क्रियान्वयन माह नवंबर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.12 में दर्शित है।

तालिका 16.12 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	—
	अनुसूचित जनजाति	—	—
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	—
	अनुसूचित जनजाति	—	—
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	22.00
	अनुसूचित जनजाति		57.00

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :- पोस्ट मेट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है, इसके अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रुपये 700/- की दर से उपलब्ध कराई जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.13 में दर्शित है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 16.13 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	139.47
	अनुसूचित जनजाति	—	481.16
	पिछड़ा वर्ग	—	23.86
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	139.47
	अनुसूचित जनजाति	—	481.16
	पिछड़ा वर्ग	—	23.86
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	151.53
	अनुसूचित जनजाति		516.46
	पिछड़ा वर्ग		29.40

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना:—

16.4.10.1 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :— यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 नर्सिंग प्रशिक्षण योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	65	45.19
	अनुसूचित जनजाति	84	55.64
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	253	139.01
	अनुसूचित जनजाति	365	206.57
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	288	107.86
	अनुसूचित जनजाति	497	180.75

16.4.10.2 हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :— राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर होस्टेज, एविएशन हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006-07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013-14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.15 में दर्शित है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका 16.15 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	51	25.51
	अनुसूचित जनजाति	25	12.47
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	113	31.67
	अनुसूचित जनजाति	45	15.78
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	26	12.44
	अनुसूचित जनजाति	08	3.83

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :- इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से योजना लागू की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.16 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.16 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	24	3.60
	अनुसूचित जनजाति	48	7.20
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	0	0.09
	अनुसूचित जनजाति	0	0.81
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	0	0.00
	अनुसूचित जनजाति	0	0.00

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :- प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.17 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	86	30.00
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	240	15.61
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	56	8.40

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास :- वर्ष 2015-16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :-

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006-07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि रु. 1,00,000 दिया जाता है।
- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रु. 10,000 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।
- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला- बलौदा बाजार में किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रु. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रु. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रु. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चिर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।
- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार-छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि रु. 2 लाख से पुरस्कृत तथा प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।
- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार-छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट

तालिका 16.18 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास			
(राशि लाख में)			
वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	148	148.00
	2. आदिवासी लोककला दलों को सहायता	256	25.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.50
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	280	280.00
	2. आदिवासी लोककला दलों को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	--	8.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.35
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	164	164.20
	2. आदिवासी लोककला दलों को सहायता	236	23.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.70

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.18 में दर्शित है।

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :- अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रु. 1.0 लाख प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना हेतु कुल राशि रु. 28.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.19 में दर्शित है।

तालिका 16.19 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	—	—
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		—	—
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)		—	—
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	—
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		—	—
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)		1	1.00

16.4.14 राजीव युवा उत्थान योजना :- वर्ष 2003 से यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, इसके माध्यम से 50 सीटें जिला-रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100-100 सीटें स्वीकृत हैं। ट्रायबल यूथ हास्टल द्वारका नई दिल्ली में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2018-19 में ड्राॅपर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.20 में दर्शित है।

तालिका क्र. 16.20 राजीव युवा उत्थान योजना (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	14	21.43
	अनुसूचित जनजाति	22	35.72
	पिछड़ा वर्ग	08	14.28
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	14	36.04
	अनुसूचित जनजाति	22	60.07
	पिछड़ा वर्ग	08	24.02
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	14	6.00
	अनुसूचित जनजाति	22	10.00
	पिछड़ा वर्ग	08	4.00

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के 04 घटक हैं:-

- **आस्था:-** नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए अध्ययन कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के 220 बालक एवं कन्या दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित गुरुकुल आवासीय विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।
- **सहयोग:-** इस योजना अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाड़ा मुख्यालय योजना सम्मिलित है।
- **निष्ठा:-** इसके तहत पीडित परिवारों के लिए कक्षा 01 से 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत हैं। वर्ष 2020-21 से यह योजना बंद कर दी गई है।
- **प्रयास:-** इसके तहत नक्सल प्रभावित 16 जिले के 10 वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को कक्षा 11वीं 12वीं तक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ जे.ई.ई.(मेन/एड्वास) नीट/पी.ई.टी./सी.ए./सी.एस./क्लैट/एन.टी.एस.सी. इत्यादि हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा तथा जशपुर जिले में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं जिसमें कुल 2,859 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना:-

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम :- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 09 माडा पाकेट एवं 02 लघु अंचल तथा 18 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ गठित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.21 पर दर्शित है।

तालिका 16.21 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	27 कार्य	8432.80
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	03 कार्य	336.26

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरचना/व्यक्ति मूलक परिवार मूलक कार्य पूंजी मद एवं राजस्व मद के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

तालिका क. 16.22 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनु. जनजाति	10 कार्य	7580.14
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनु. जनजाति	15 कार्य	11669.00
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनु. जनजाति	36 कार्य	6661.38

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :- पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण द्वारा उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशु पालन, मत्स्य पालन, बाड़ी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं ली जाती हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.23 में दर्शित है।

तालिका 16.23 पण्डो एवं भुंजिया विकास (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	07 कार्य	70.00
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	03 कार्य	40.00

16.4.16.4 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :- केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा-आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्हलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों का बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रीय 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

तालिका 16.24 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	194 ग्राम	3898.80
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	194 ग्राम	11495.18
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	115 ग्राम	3860.00

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :- भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए “मल्टी सेक्टरल प्रोग्राम” (संशोधित योजना का नाम-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासांबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सड़क, पेयजल और आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.25 में दर्शित है:-

तालिका 16.25 मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम			
(राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अल्प संख्यक वर्ग	05 कार्य	22.43
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	17 कार्य	396.55
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	24 कार्य	447.54

16.4.17 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:-

- **अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता :-** सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम धारा के तहत राहत सहायता एवं पुर्नवास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक पर सद्भावना शिविरों का आयोजना किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

तालिका 16.26 अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	642	1140.00
	अनुसूचित जनजाति	331	445.00
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	1408	2609.20
	अनुसूचित जनजाति	790	824.36
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	620	1650.00
	अनुसूचित जनजाति	320	401.05

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :- योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ व्यक्तिमूलक / परिवारमूलक एवं रोजगार वृद्धि कारक कराये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

तालिका 16.27 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह			
(राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनु. जनजाति	06 कार्य	639.39
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनु. जनजाति	19 कार्य	1595.83
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनु. जनजाति	20 कार्य	1628.71

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

- **स्वदेश दर्शन योजना (ट्रायबल टूरिज्म सर्किट) :-** भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से राशि रु. 96.10 करोड़ की योजना में कार्य कराया जा रहा है। भारत सरकार से 84.81 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस सर्किट में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सर्किट में जशपुर, कुनकुरी, मैनापाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथियानवागांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल है। अभी तक 09 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- **प्रशाद योजना —** भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत राशि रु. 43.33 करोड़ की लागत से “माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास” परियोजना स्वीकृत करायी गयी है। इस परियोजना में माँ बम्लेश्वरी देवी पहाड़ी पर एवं नीचे तथा प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर विकास कार्य प्रस्तावित है। उक्त योजना में भारत सरकार से रु. 12.16 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। जिससे कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की स्वीकृति से “डोंगरगढ़” देश के चुनिंदा महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। इस योजना का मुख्य आकर्षण पहाड़ी के नीचे में बनने वाला पिल्लिग्रिम फेसिलिटेशन सेंटर है जिसके भवन का डिजाइन श्री यंत्र के आकार का है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

तालिका क. 16.28 विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी							
(राशि लाख रु. में)							
क्र.	प्रस्तावित कार्य	(अप्रैल 20 से सितम्बर 20)		(अप्रैल 20 से मार्च 21)		(अप्रैल 21 से सितम्बर 21)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट का क्रियान्वयन।	प्रगति पर	7802.45	प्रगति पर	526.76	प्रगति पर	358.99
2	प्रसाद योजना	—	—	कार्य प्रारंभ	—	प्रगति पर	432.00
3	ग्राम सण्डी स्थित माता हिंगलाजिन एवं सिद्धनाथ मंदिर का पर्यटन विकास के तहत सामुदायिक भवन (महिला एवं पुरुष शौचालय सहित), प्रवेश द्वार, पेयजल हेतु प्लेटफार्म, पाइप लाइन सहित समिति द्वारा निर्मित पानी टंकी/बोर से जोड़ना/लैण्ड डेव्हलपमेंट एवं प्लांटेशन कार्य।	प्रगति पर	—	प्रगति पर	—	प्रगति पर	—
4	जोगी बाबा मेला स्थल ग्राम झांकि वि.ख. नवागढ़ में चबूतरा निर्माण एवं बाउंड्रीवाल फेंसिंग कार्य।	प्रगति पर	—	कार्य पूर्ण	4.78	—	—
5	सरोधा दादर में एडवेंचर एक्टिविटी उपकरण	प्रगति पर	—	प्रगति पर	—	प्रगति पर	8.70
6	ग्राम जबर्रा में होमस्टे कैपेनिंग उपकरण एवं सौर प्लांट की स्थापना	प्रगति पर	—	प्रगति पर	11.095	प्रगति पर	—
7	लुतरा शरीफ दरगाह में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य विषयक।	प्रगति पर	—	प्रगति पर	4.55	प्रगति पर	—
8	1. ग्राम गाड़ागौरी वि.ख. चारामा जिला कांकर में स्थित गढ़शीतला मंदिर में पेयजल एवं सीढ़ी निर्माण (5.00 लाख) 2. ग्राम आंवरी स्थित रानी मां में उद्यान, पगोड़ा एवं शेड निर्माण कार्य। (10.00 लाख)	प्रगति पर	3.57	कार्य पूर्ण	14.28	—	—
9	बूढ़ादेव पहाड़ी डोंगरगढ़ में शौचालय निर्माण एवं ज्योति कक्ष निर्माण। मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा।	—	—	निर्माण स्थल के संबंध में दो समुदायों में आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण उक्त कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।			
10	ग्राम जैमरा चैतुरगढ़ मेला स्थल एवं महामाया मंदिर ग्राम लाफा लाफागढ़ में शेड निर्माण	प्रगति पर	—	प्रगति पर	2.00	प्रगति पर	—

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। “जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969” के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण “छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु पंजीयन नियम 2001” के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म-मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 28 जिलों में 11658 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म-मृत्यु पंजीयन करते हैं।

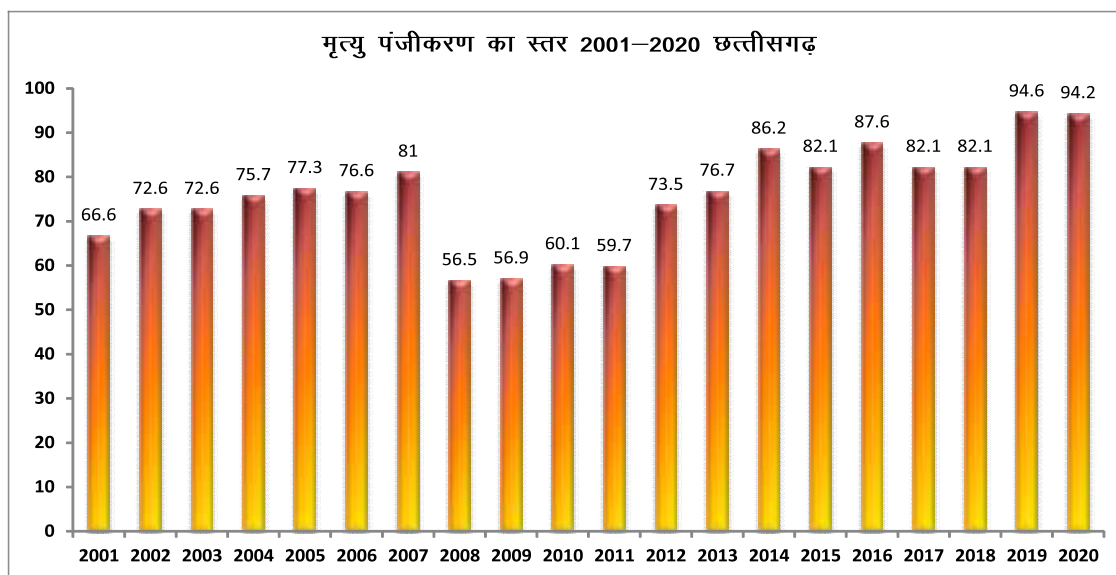
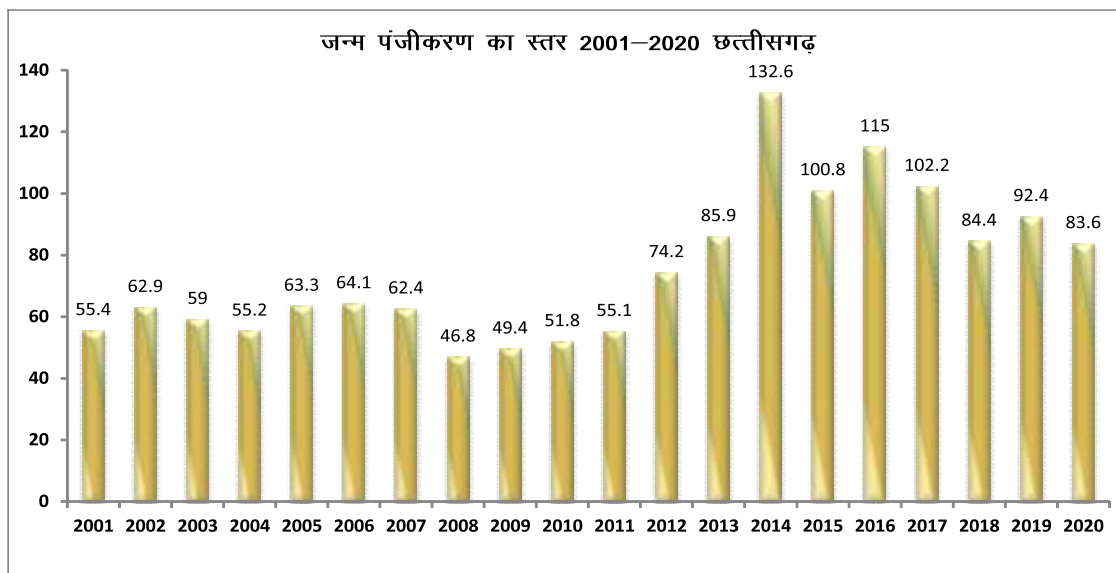
समस्त पंजीयन इकाइयों में पंजीयन से संबंधित वैधानिक भाग सुरक्षित रखा जाता है। इसी के आधार पर प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate) प्रदान की जाती है। सांख्यिकी भाग जिला रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाता है जिसके आधार पर विश्लेषण कर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो प्रतिवर्ष राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भेजी जाती है।

राज्य में कुल 169 शहरी इकाइयां हैं, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा — जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म-मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

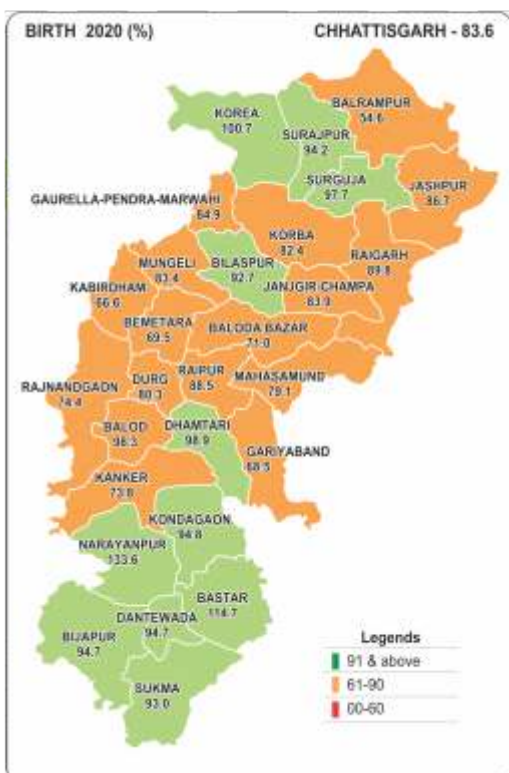
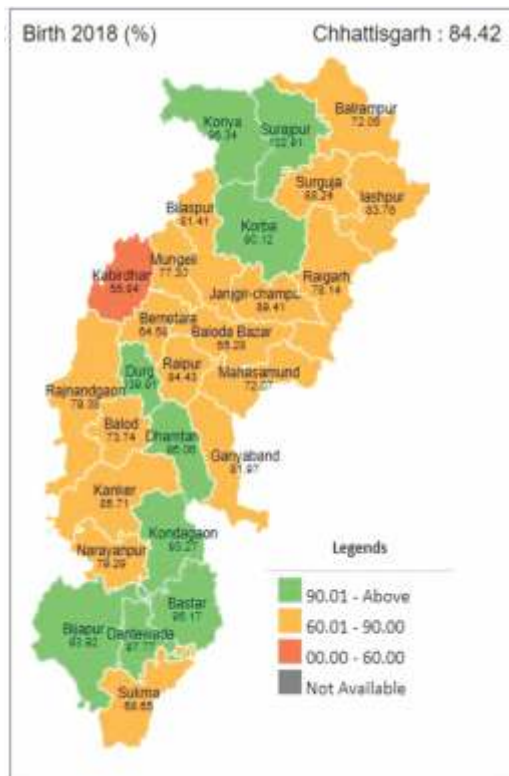
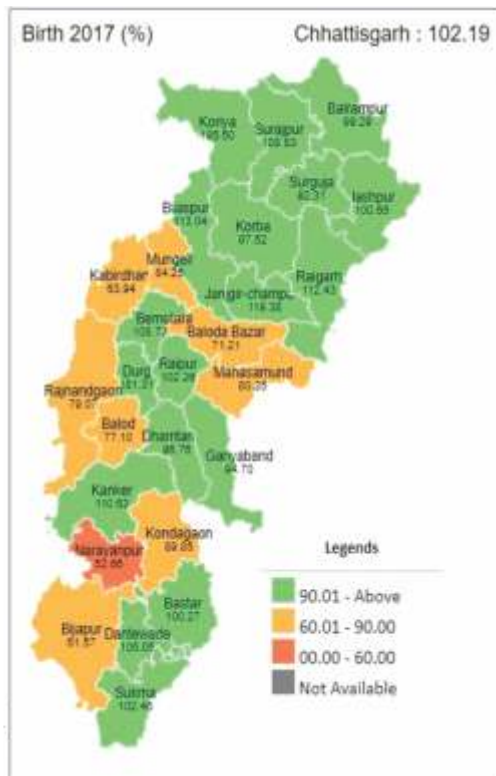
समस्त पंजीयन इकाइयों द्वारा जन्म-मृत्यु के ऑनलाईन पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल पर किया जाता है एवं संचालनालय द्वारा उक्त डाटा को वेबपोर्टल से डाउनलोड एवं विश्लेषण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22



Source: Annual Vital Reports

► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22



► आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2021-22

